बैंकोंमें सुधारको गति

भारतको वर्ष २०४७ तक विकसित राष्ट्र बनानेका लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस दिशामें बहुआयामी सुधारोंके लिए सक्रियता बढ़ा दी गयी है। इसी क्रम में बैंकिंग क्षेत्रमें व्यापक सुधारके एजेण्डेको प्राथमिकता दी गयी है। भारतके बैंकिंग क्षेत्रमें सुधारकी दिशा अब केवल बैंकोंकी वित्तीय स्थिति सुधारनेकी तक सीमित नहीं है। विकसित भारतकी जरुरतोंके अनुरूप बैंकिंग व्यवस्थाको अधिक सक्षम, वैश्विक स्तरपर प्रतिस्पर्धा, डिजिटल, सुरक्षित और समावेशी बनानेकी तैयारी स्वागतयोग्य है। शुक्रवार ३० अक्तूबरको वित्त मंत्रालयने एक उच्चस्तरीय बैठक आहूत की जिसमें बैंकिंग क्षेत्रमें सुधारके एजेण्डेपर गहन मंत्रणा हुई। उसी दिन भारतीय रिजर्व बैंकने भी गवर्नर संजय मेहरोत्राकी अध्यक्षतामें केन्द्रीय बोर्डकी बैठक की, जिसमें बैंकिंग क्षेत्रमें सुधार मुख्य मुद्दा रहा। केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर बैंकिंग क्षेत्रको २०४७ तक विकसित भारतके लक्ष्यसे जोड़नेकी दिशामें आगे बढ़ रहे हैं। वस्तुत: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब २०२६-२७ का बजट संसदमें प्रस्तुत किया था तभी उन्होंने उच्च स्तरीय समिति बनानेकी भी घोषणा की थी। केन्द्र सरकार यह भी चाहती है कि विश्वके शीर्ष पांच बैंकोंमें कम से कम एक भारतीय बैंक भी उसमें शामिल हो। सुधारका नया चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षोंमें सार्वजनिक क्षेत्रके बैंकोंकी स्थितिमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वित्तवर्ष २०२५-२६ में इन बैंकोंका संयुक्त लाभ १.९८ लाख करोड़ रुपयेपर पहुंच गया और सकल एनपीए १.९३ प्रतिशतके ऐतिहासिक निचले स्तरपर आ गया है। सरकारका नया एजेण्डा इसी परिवर्तनको दर्शाता है कि संकटसे उबरने वाली बैंकिंग से विकासको गति देने वाली बैंकिंगकी ओर ले जानेको हम संकल्पित हैं। इसके साथ ही वैश्विक स्तरपर बैंकको मजबूत बनाना, बैंकिंगमें पूंजी की उपलब्धता, एआई और डिजिटल बैंकिंगसे जुड़े अनेक विषय भी सुधारके क्षेत्रमें आते हैं। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्रके बैंकोंकी कार्यप्रणालीमें उल्लेखनीय सुधार करनेकी जरुरत है। बैंकोंकी स्वायत्तताके साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित करना है। कृषि, छोटे उद्योग, स्टार्टअप, महिला उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्थापर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा। ग्राहक सुरक्षा सबसे बड़ा सुधारका क्षेत्र है। सुधारकी दिशामें अनेक चुनौतियां भी हैं, जिनपर विशेष ध्यान देना होगा तभी हम भारतीय बैंकोंको विकसित भारतके लक्ष्यके अनुरूप बना सकेंगे।

सराहनीय उपलब्धि

अन्तरिक्षमें लगातार बढ़ती भारतकी ताकत हर देशवासीके लिए गर्वकी बात है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संघटन (इसरो) का शुक्रवार देर रात नौवहन उपग्रह 'एनवीएस-०३' का सफल प्रक्षेपण और निर्धारित कक्षामें स्थापित किया जाना इसका प्रमाण है। इसीके साथ अब भारतके पास कक्षामें चार नेविगेशन उपग्रह हो गये जो इसरोकी बड़ी उपलब्धि है। इसरो अध्यक्ष बी.नारायणन के अनुसार बेहतर पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाओंके लिए कमसे कम चार उपग्रहोंकी आवश्यकता होती है, जिसे इस प्रक्षेपणके बाद भारतने हासिल कर लिया। इससे लोकेशन-नेविगेशन सुविधाएं मजबूत होंगी। अन्तरिक्ष में 'नाविक' के इनचार उपग्रहोंने भारतकी 'दृष्टि' को नयी रोशनी दी है। 'नाविक' के इन चार उपग्रहोंसे १०,४०० रेल इंजन और ६४ हजार मछली पकड़ने वाली नौकाओंकी निगरानीकी जा सकेगी। 'नाविक' जीपीएसका भारतीय संस्करण है जिसका दायरा १,५०० किलोमीटर तक फैला है। तकनीकी बाधाओंसे बचनेके लिए एनवीएस-०३ उपग्रहके तीन पाइरो वाल्व खुले रखकर भेजा गया है, क्योंकि २०२५ में प्रक्षेपित एनवीएस श्रृंखलाका दूसरा उपग्रह एनवीएस-०२ मिशन असफल हो गया था। पाइरो वाल्व अन्तरिक्षयानकी प्रोपल्शान सिस्टमका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जो तकनीकी बाधाओंको नियंत्रित करते हैं। इसरो अब अगले पांच महीनेमें एनवीएस-०४ और अगले दस महीनोंमें एनवीएस-०५ का प्रक्षेपण करनेकी तैयारी कर रहा है ताकि उपग्रह समूहको मजबूत किया जा सके। यह इसलिए भी जरूरी है कि निर्बाध सेवाएं और सटीक स्थिति निर्धारण सुनिश्चित करनेके लिए कक्षामें सात उपग्रहोंको तैनात करना होगा। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने इस प्रक्षेपणकी सफलतापर इसरोके वैज्ञानिकों और इंजीनियरोंको बधाई दी है। इससे भारतीय उपमहाद्वीपमें सामरिक और नागरिक सेवाओंके लिए लोकेशन और नेविगेशन सुविधाएं मजबूत होंगी। इसकी सराहना की जानी चाहिए।

लोक संवाद

एकताकी भावना

महोदय,-भारतमें बहुतसे महापुरुष हुए। इन महापुरुषोंने भारतको ही नहीं, बल्कि दुनियाको अच्छे मार्गपर ले जानेके लिए बहुतसे काम किये और दुनियाके लिए प्रेरक बने। इन्हीं महापुरुषोंमेंसे एक थे सरदार वल्लभभाई पटेल, जिनका जन्मदिन एकताकी भावनाको बढ़ानेके रूपमें भी मनाया जाता है, जो कि ३१ अक्तूबरको होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेलने देशको आजाद करवानेके साथ-साथ देशकी एकताको मजबूत करनेमें मुख्य भूमिका निभायी थी। इन्होंने किसानोंको उनका हक अंग्रेजोंसे दिलानेके लिए काम किये थे। सरदार वल्लभ भाई पटेलको आज भी जिस मुख्य कार्यके लिए याद किया जाता है वो है देसी रियासतोंका एकीकरण। आज भारतको उनके विचारोंको कार्यरूप देनेकी जरूरत है। **- राजेश, वाया ईमेल।**

गहरी होती सामाजिक विषमताकी खाई

दुनिया आज ऐसे विरोधाभासके दौरसे गुजर रही है, जहां एक ओर विकास और आधुनिकताके नये कीर्तिमान स्थापित किये जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय विनाशकी चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रश्न यह है कि जब दुनियाके पास पर्याप्त संसाधन हैं, तब भी करोड़ों लोग जीवनकी बुनियादी आवश्यकताओंके लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं।

❐ **ललित गर्ग**

अंतरराष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैमकी रिपोर्ट डिजास्टर डिवाइड इसी प्रश्नका एक असहज, किन्तु विचारोत्तेजक उत्तर प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट बताती है कि जलवायु संकट केवल प्रकृतिकी नाराजगी नहीं, बल्कि आर्थिक असमानता, अनियंत्रित उपभोग और संसाधनोंपर मुट्ठीभर लोगोंके बढ़ते नियंत्रणका परिणाम भी है। दुनियाकी लगभग ८० लाख आबादी वाले सबसे धनी ०.१ प्रतिशत वर्गकी जीवनशैली और निवेशसे होने वाला कार्बन उत्सर्जन करोड़ों नहीं, अरबों लोगोंके जीवनको प्रभावित कर रहा है। रिपोर्टके अनुसार यह वर्ग दुनियाके सबसे गरीब ४४ प्रतिशत लोगोंकी तुलनामें अधिक कार्बन प्रदूषणके लिए जिम्मेदार है। यह असमानता केवल आंकड़ोंका अन्तर नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनहीनताका ऐसा दस्तावेज है, जिसमें कुछ लोगोंकी विलासिताकी कीमत पूरी मानवता चुका रही है। निजी विमान, विशाल नौकाएं, अत्यधिक ऊर्जा खपत और प्रदूषणकारी उद्योगोंमें निवेश आधुनिक अमीरीके प्रतीक बन गये हैं, जबकि दूसरी ओर गरीब आबादी स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी और दो वक्तकी रोटीके लिए संघर्ष कर रही है। सवाल यह नहीं कि किसी व्यक्तिके पास कितनी संपत्ति है, बल्कि यह है कि उसकी संपन्नताका सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्य कौन चुका रहा है। इस संकटका सबसे भयावह पक्ष यह है कि जलवायु आपदाएं भी अमीर और गरीबके बीच भेदभाव करने लगी हैं। बाढ़ एक ही समयमें अमीरकी आलीशान कोठी और गरीबकी झोपड़ीतक पहुंचती है, लेकिन दोनोंके परिणाम अलग होते हैं। अमीर सुरक्षित स्थानोंपर चले जाते हैं, बीमा और आधुनिक सुविधाओंसे नुकसानकी भरपाई कर लेते हैं, जबकि गरीब अपना घर, खेत, पशुधन और आजीविका गंवाकर वर्षों पीछे चला जाता है। ऑक्सफैमके अनुसार, अधिक आर्थिक असमानता वाले देशोंमें बाढ़से होने वाली मौतें सात गुनातक अधिक होती हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट बताती है कि दुनियाके सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगोंका उत्सर्जन भविष्यमें लगभग १९ लाख अतिरिक्त गर्मी-संबंधी मौतोंका कारण बन सकता है। इनमें ७८ प्रतिशत मौतें निम्न एवं निम्न-मध्यम आय वाले देशोंमें होनेका अनुमान है।



ऑक्सफैमकी 'डिजास्टर डिवाइड' रिपोर्ट दुनियाके सामने एक बुनियादी नैतिक प्रश्न खड़ा करती है-क्या विकासका अर्थ कुछ लोगोंकी असीमित समृद्धि और बहुसंख्यक मानवताकी बढ़ती विवशता है। पृथ्वी किसी एक वर्गकी जागीर नहीं, न ही उसके संसाधनोंपर किसी मुट्ठीभर लोगोंका एकाधिकार हो सकता है। याद रखना होगा कि जब समाजमें विषमताकी खाईं बहुत गहरी हो जाती है, तब असंतोषकी आग सीमाओंमें नहीं बंधती। धरतीको बचाना है तो विकासकी दिशा बदलनी होगी, समृद्धिको संवेदनासे जोड़ना होगा और अर्थव्यवस्थाको मानवताके प्रति जवाबदेह बनाना होगा।

आर्थिक असमानताका यह अंतर केवल पर्यावरणतक सीमित नहीं है। जब समाजमें संसाधनों, अवसरों और अधिकारोंका वितरण अन्यायपूर्ण हो जाता है, तब असंतोष जन्म लेता है। बेरोजगारी, महंगी, खाद्य संकट, जल संकट और विस्थापन सामाजिक तनावको बढ़ाते हैं। धीरे-धीरे यही तनाव आक्रोश, विद्रोह, अपराध, सामुदायिक संघर्ष और हिंसाका रूप ले सकता है। यह कहना उचित नहीं होगा कि प्रत्येक हिंसाके पीछे केवल अमीरी-गरीबीका अंतर है, लेकिन जब विकासका लाभ सीमित हाथोंमें सिमटता है और संकटका बोझ बहुसंख्यक आबादीपर पड़ता है, तब सामाजिक शांतिकी नींव कमजोर होना स्वाभाविक है। विडंबना यह है कि कुछ बड़े निवेशक पहले प्रदूषणकारी उद्योगोंसे मुनाफा कमाते हैं और फिर उन्हीं आपदाओंसे निबटने, सफाई तथा पुनर्निर्माणके कारोबारमें लाभ अर्जित करते हैं। ऑक्सफैमका 'डिस्ट्रॉय एंड रीबिल्ड इंडेक्स' २१७ कम्पनियोंके माध्यमसे इसी दोहरे मुनाफेकी पड़ताल करता है। यह सचमुच ऐसी व्यवस्थापर प्रश्नचिह्न है, जहां किसीके लिए आपदा भी अवसर बन जाती है और किसीके लिए जीवनभरका अभिशाप। भारतके संदर्भमें यह चेतावनी और भी गम्भीर है। भारतकी विशाल आबादीका बड़ा हिस्सा कृषि, निर्माण, छोटे व्यवसायों और असंघटित क्षेत्रपर निर्भर है। किसान अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और तापमान वृद्धिसे जूझ रहा है। मजदूर भीषण गर्मीमें काम करनेको विवश है और महानगरोंकी झुग्गी-बस्तियोंमें रहने वाले परिवार जलभराव तथा गर्मीकी दोहरी मार झेल रहे हैं। विश्व बैंकके अनुसार भारतकी ८० प्रतिशतसे अधिक आबादी ऐसे जिलोंमें रहती है जो जलवायु परिवर्तनसे उत्पन्न आपदाओंके जोखिममें हैं। वहीं, देशके ५७ प्रतिशत जिलोंमें रहने वाली लगभग ७६ प्रतिशत आबादी अत्यधिक गर्मीके उच्च या बहुत उच्च जोखिमका सामना कर रही है। भारतके लिए चुनौती केवल आर्थिक विकासकी गति बढ़ाना नहीं, बल्कि विकासको न्यायपूर्ण, समावेशी और पर्यावरणके अनुकूल बनाना है। विकसित भारत २०४७ का स्वप्न तभी सार्थक होगा, जब विकासकी चमक अंतिम पंक्तिमें खड़े व्यक्तिके जीवनतक पहुंचे। यदि एक ओर महानगरोंमें विलासिता और उपभोगके नये कीर्तिमान बनें और दूसरी ओर गांवोंमें किसान पानी, बिजली और आजीविकाके लिए संघर्ष करता रहे तो विकासकी तस्वीर अधूरी ही रहेगी। विश्वगुरु बननेकी आकांक्षा रखने वाले भारतको दुनियाके सामने यह उदाहरण प्रस्तुत करना होगा कि आर्थिक समृद्धि और प्रकृतिके संरक्षणके बीच संतुलन संभव है। इसके लिए कुछ बुनियादी प्राथमिकताएं आवश्यक हैं। संपन्न वर्ग और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगोंकी जवाबदेही तय हो, विलासितापूर्ण उपभोगपर उचित कर व्यवस्था बने, स्वच्छ ऊर्जाको प्रोत्साहन मिले और जल, जंगल तथा जमीनके संरक्षणको विकासकी अनिवार्य शर्त बनाया जाय। साथ ही जलवायु आपदाओंसे प्रभावित किसानों, मजदूरों और कमजोर समुदायोंके लिए सामाजिक सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा पुनर्वासकी प्रभावी व्यवस्था हो। विकासका लाभ केवल पूंजीके स्वामियोंतक सीमित न रहे, बल्कि श्रम करने वाले हाथोंतक भी पहुंचे। भारतकी सांस्कृतिक चेतनामें 'सर्वे भवन्तु सुखिनः', 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'अपरिग्रह' जैसे जीवन-मूल्य सदियोंसे प्रतिष्ठित रहे हैं। महात्मा गांधीका 'सादा जीवन, उच्च विचार' केवल व्यक्तिगत आचरणका संदेश नहीं, बल्कि संसाधनोंके विवेकपूर्ण उपयोग और सामाजिक उत्तरदायित्वका दर्शन है। जैन दर्शनका अपरिग्रह भी यही सिखाता है कि आवश्यकतासे अधिक संग्रह अंतत: समाजमें असंतुलन पैदा करता है। प्रकृति हमारी संपत्ति नहीं, आने वाली पीढ़ियोंकी धरोहर है। अंतत: ऑक्सफैमकी 'डिजास्टर डिवाइड' रिपोर्ट दुनियाके सामने एक बुनियादी नैतिक प्रश्न खड़ा करती है-क्या विकासका अर्थ कुछ लोगोंकी असीमित समृद्धि और बहुसंख्यक मानवताकी बढ़ती विवशता है। पृथ्वी किसी एक वर्गकी जागीर नहीं, न ही उसके संसाधनोंपर किसी मुट्ठीभर लोगोंका एकाधिकार हो सकता है। आज आवश्यकता अमीरीको अपराध माननेकी नहीं, बल्कि अमीरीके साथ जवाबदेही जोड़नेकी है। याद रखना होगा कि जब समाजमें विषमताकी खाईं बहुत गहरी हो जाती है, तब असंतोषकी आग सीमाओंमें नहीं बंधती। धरतीको बचाना है तो विकासकी दिशा बदलनी होगी, समृद्धिको संवेदनासे जोड़ना होगा और अर्थव्यवस्थाको मानवताके प्रति जवाबदेह बनाना होगा। क्योंकि जिस विकासमें प्रकृति सुरक्षित नहीं और मनुष्य सम्मानित नहीं, वह विकास नहीं, विनाशकी प्रस्तावना है।

आदिवासियोंके अस्तित्वका संकट

विकास किसी भी देशकी प्रगतिका आधार होता है, लेकिन विकासकी राहमें जब लोगोंके घर, संस्कृति और प्राकृतिक विरासत दांवपर लगने लगें, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर विकास किसके लिए किया जा रहा है।

❐ **महेन्द्र तिवारी**

अरुणाचल प्रदेशकी सियांग नदीपर प्रस्तावित विशाल जलविद्युत परियोजनाको लेकर उठ रहा विरोध इसी सवालको हमारे सामने रखता है। एक ओर सरकार इसे बिजली उत्पादन, जल सुरक्षा और राष्ट्रीय हितोंसे जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना मानती है तो दूसरी ओर स्थानीय आदिवासी समुदायोंको अपनी पुश्तैनी जमीन, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान खोनेका भय सता रहा है। अरुणाचल प्रदेशके सियांग क्षेत्रमें प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजनाकी क्षमता ११,२०० मेगावाट बतायी गयी है। यह भारतकी सबसे बड़ी प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाओंमेंसे एक है। राष्ट्रीय जलविद्युत निगमको इससे संबंधित प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययनकी जिम्मेदारी दी गयी है। सरकारका तर्क है कि इस परियोजनासे बड़े पैमानेपर बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त नदीके जलका भंडारण और प्रवाहका नियमन करनेमें भी सहायता मिल सकती है। देशकी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओंको देखते हुए ऐसी परियोजनाओंका महत्व नकारा नहीं जा सकता। लेकिन किसी परियोजनाकी उपयोगिता केवल उससे मिलने वाली बिजली या आर्थिक लाभसे तय नहीं होती। यह भी देखना आवश्यक है कि उसके निर्माणसे किन लोगोंको लाभ मिलेगा और किन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सियांग घाटीमें रहने वाले आदि समुदायके लोगोंकी आशंकाएं इसी बिन्दुसे जुड़ी हैं। स्थानीय संघटनोंके अनुसार प्रस्तावित जलाशयके कारण २७ गांव डूब सकते हैं और अनेक अन्य गांवोंपर भी प्रभाव पड़ सकता है। प्रभावित होने वाले परिवारोंके लिए यह केवल मकान बदलनेका मामला नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जीवनशैलीसे बिछुड़नेका संकट है। आदिवासी समुदायोंका प्रकृतिके साथ संबंध सामान्य आर्थिक संबंधोंसे कहीं अधिक गहरा होता है। उनकी जमीनमें केवल खेत और मकान नहीं होते, बल्कि पीढ़ियोंकी स्मृतियां, पूर्वजोंकी विरासत और सामाजिक परम्पराएं भी जुड़ी होती हैं। नदी उनके लिए पानीका स्रोत भर नहीं होती, बल्कि जीवन और संस्कृतिका अभिन्न अंग होती है। सियांग नदीके आसपास रहने वाले अनेक लोगोंकी आजीविका खेती, बागवानी, पशुपालन और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनोंपर निर्भर है। यदि उन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ी तो उनके सामने रोजगार, भोजन, सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक निरन्तरतासे जुड़े अनेक प्रश्न खड़े हो सकते हैं। परियोजनाको लेकर पर्यावरणीय चिन्ताएं भी कम गम्भीर नहीं हैं। हिमालयका यह क्षेत्र भूकम्पकी दृष्टिसे संवेदनशील है। इतने बड़े बांधके निर्माणसे पहले भूगर्भीय संरचना, भूकम्पीय जोखिम, नदीके प्राकृतिक प्रवाह, वन्यजीवों और जैव विविधतापर पड़ने वाले प्रभावोंका गहन वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। बड़े जलाशयोंसे स्थानीय पारिस्थितिकीमें बदलाव आ सकता है। नदीके प्रवाहमें परिवर्तनका असर मछलियों, वनस्पतियों, कृषि और नदीपर निर्भर समुदायोंपर पड़ सकता है। हालांकि इन संभावित प्रभावोंकी वास्तविक सीमाका निर्धारण स्वतंत्र और विस्तृत वैज्ञानिक आकलनसे ही किया जा सकता है। इस विवादका एक महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय सुरक्षा भी है। तिब्बतमें चीन यारलुंग त्सांगपो नदीपर विशाल जलविद्युत परियोजना विकसित कर रहा है। यही नदी भारतमें प्रवेश करनेके बाद सियांग कहलाती है और आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालीका हिस्सा बनती है। चीनकी परियोजनाको लेकर भारतमें नदीके प्रवाह, जल प्रबंधन और संभावित रणनीतिक जोखिमोंपर चिन्ता व्यक्त की जाती रही है। ऐसेमें सियांगपर जल भंडारणकी भारतीय परियोजनाको राष्ट्रीय सुरक्षाके दृष्टिकोणसे भी देखा जा रहा है। फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय लोगोंके अधिकारोंको एक-दूसरेके विरोधमें खड़ा करना उचित नहीं होगा। देशकी सीमाओंकी सुरक्षा जितनी आवश्यक है, उतना ही जरूरी उन नागरिकोंके अधिकारोंकी रक्षा करना भी है जो सीमावर्ती क्षेत्रोंमें रहते हैं। किसी परियोजनाका रणनीतिक महत्व अपने आपमें स्थानीय समुदायोंकी आशंकाओंको समाप्त नहीं कर देता। सरकारको यह स्पष्ट करना होगा कि परियोजनासे होने वाले सम्भावित लाभोंके साथ-साथ उसके सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमोंका समाधान किस प्रकार किया जायगा। अक्तूबर २०२६ में इस परियोजनाके विरोधने व्यापक रूप ले लिया है। स्थानीय संघटनों और युवाओंने सर्वेक्षण रोकने, गिरफ्तार कार्यकर्ताओंको रिहा करने तथा प्रभावित समुदायोंसे सार्थक बातचीत करनेकी मांग उठायी है। २३ अक्तूबरको पासीघाटमें विरोध प्रदर्शनके दौरान हिंसा और संपत्तिको नुकसान पहुंचनेकी घटनाएं भी सामने आयीं। हिंसा किसी समस्याका समाधान नहीं है और सार्वजनिक संपत्तिको नुकसान पहुंचाना उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन विरोधके दौरान हुई हिंसाके कारण उन मूल सवालोंको भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, जिनके कारण स्थानीय लोगोंमें असंतोष पैदा हुआ है। सरकारका कहना है कि फिलहाल परियोजनाकी व्यवहार्यताका अध्ययन किया जा रहा है। सर्वेक्षणका अर्थ अंतिम निर्माण स्वीकृति नहीं है। तकनीकी दृष्टिसे यह अंतर महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थानीय लोगोंकी आशंकाको भी समझना होगा। उनके लिए जमीनपर सर्वेक्षण और ड्रिलिंगकी शुरुआत भविष्यमें होने वाले बड़े बदलावोंकी आशंका पैदा करती है। इसलिए केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि अभी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। सरकारको पारदर्शिताके साथ जानकारी साझा करनी चाहिए और स्थानीय लोगोंके प्रश्नोंका स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। इस समस्याका समाधान संवाद, विश्वास और न्यायपूर्ण प्रक्रियामें छिपा है। परियोजनासे प्रभावित होने वाले प्रत्येक गांव और परिवारकी स्थितिका निष्पक्ष आकलन किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय अध्ययन स्वतंत्र विशेषज्ञोंकी निगरानीमें हों और उनके निष्कर्ष सार्वजनिक किये जायं। स्थानीय समुदायोंकी सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जाय। यदि परियोजना आगे बढ़ती है तो पुनर्वास और मुआवजेकी व्यवस्था केवल आर्थिक भुगतानतक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि प्रभावित परिवारोंकी आजीविका, सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक आवश्यकताओंको भी ध्यानमें रखना चाहिए। विकासका वास्तविक अर्थ केवल बांध बनाना, बिजली पैदा करना या आर्थिक आंकड़े बढ़ाना नहीं है। विकास वह है जो लोगोंके जीवनको बेहतर बनाये, उनकी गरिमाकी रक्षा करे और प्रकृतिके साथ संतुलन स्थापित करे। सियांग परियोजनाके सामने चुनौती यही है कि राष्ट्रीय हितों और स्थानीय अधिकारोंके बीच ऐसा रास्ता निकाला जाय जिसमें किसी एककी कीमतपर दूसरेको लाभ न मिले। नदीकी धाराको नियंत्रित करनेसे पहले उससे जुड़े लोगोंकी आवाज सुनना जरूरी है। आखिर किसी भी लोकतंत्रकी सफलता केवल उसकी बड़ी परियोजनाओंसे नहीं, बल्कि इस बातसे तय होती है कि वह अपने सबसे दूरस्थ क्षेत्रोंमें रहने वाले नागरिकोंकी चिन्ताओंको कितनी गम्भीरतासे सुनता है।



अपरिवर्तनशील धर्म

❐ **जग्गी वासुदेव**

पंद्रह हजार वर्ष पूर्व आदियोगीने पंचभूतके बारेमें बताया था। वह अपने पहले सात शिष्योंको बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड केवल पांच तत्वोंका खेल है और यह हमारे शरीरमें किस अनुपातमें अपना खेल खेलते हैं और कैसे, यदि आप इनपर महारत हासिल कर लेते हैं तो एक तरहसे आप सृजनपर महारत हासिल कर लेते हैं। सृष्टिके एक तत्वपर महारत होनेसे भी आपकी उसतक सीधी पहुंच हो जाती है, जो सृजनका स्रोत है। जब इस विज्ञानको विस्तारमें बताया जा रहा था तो सप्तऋषि और पार्वती वहां उपस्थित थे। आदियोगी इसके पीछेकी बुद्धिमता बताते हुए कहते हैं सिर्फ चार चीजोंके साथ, आप ऐसे सूपको पका सकते हैं जिसे हम आज ब्रह्मांड कहते हैं। भौतिक रूपसे जो कुछ भी है, वह मुख्यत: चार तत्व हैं। आप अधिकांश समय पांचवें तत्वका अनुभव नहीं करते। यदि मैं आपको सिर्फ चार चीजें दूं तो क्या आप इनसे सांभर भी बना सकते हैं। सांभर बनानेके लिए भी आपको पचीस सामग्रियोंकी आवश्यकता होती है। यदि कोई चार चीजोंके साथ एक पूरे ब्रह्मांडको पका सकता है तो यह चकित कर देनेवाली बुद्धिमता है। आदियोगी इन तत्वोंपर महारत हासिल करनेके विज्ञान और तकनीकका वर्णन कर रहे थे। यह सात और एक (सप्तर्षि और पार्वती) यह सब सुन रहे थे और उन प्रदर्शनोंको देख रहे थे जो कि आदियोगी उनके लिए कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा या तो आप इन सभी चीजोंमें महारत हासिल कर सकते हैं या आप इस बुद्धिमताके प्रति समर्पण कर सकते हैं और यह आपका हो जायगा। सातों लोग इसमें महारत हासिल करनेके लिए उत्साहित थे और पार्वतीने इसके प्रति समर्पण करने और इसे खुदका हिस्सा बनानेका फैसला किया। तो इन सातोंको काम करनेके लिए दूर भेज दिया गया। पार्वतीको वहीं रहने दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस बुद्धिमताके आगे समर्पण कर दिया था और यह उनका एक हिस्सा बन गया। इन सातोंको ऋषिके रूपमें जाना गया और पार्वती देवी बन गयीं। मैं बात कर रहा हूं कि स्वयंको आगे कैसे बढ़ाया जाय! यदि आप इस बातकी गहनतामें पहुंच जाते हैं कि सब कुछ कैसे प्रकट हुआ है, भले ही आप यहां दस लाख सालोंतक रहें और लगातार अध्ययन करें, यह एक अंतहीन प्रक्रिया होगी। यह रोमांचक है, लेकिन यह एक अंतहीन प्रक्रिया है या आप बस इस अंतहीन प्रक्रियाको एक तरफ रख देते हैं और उस आयामको छूते हैं, जो इस सबका स्रोत है। यदि आप यह खेल खेलना चाहते हैं तो आप खुदको सृजनके तत्वोंके साथ शामिल करते हैं। यदि आप यह खेल नहीं खेलना चाहते हैं, यदि आप एक मैच फिक्सर हैं और सिर्फ जीतना चाहते हैं। आपको खेलमें कोई दिलचस्पी नहीं है, आप बस सफल होना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तब आप केवल उसीको स्पर्श करते हैं जो सृजनका स्रोत है। आपको तत्वोंमें खोनेकी जरूरत नहीं है।

विधान परिषद चुनाव नतीजोंके संकेत

❐ **रोहित माहेश्वरी**

उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्रकी २८ विधान परिषद सीटोंपर आये चुनावी नतीजोंने देशकी सियासतको कई महत्वपूर्ण और गहरे संकेत दिये हैं। चूंकि ये चुनाव मुख्य रूपसे शिक्षकों, स्नातकों (ग्रेजुएट्स) और स्थानीय निकायों द्वारा बैलेट पेपरके माध्यमसे चुने जाते हैं, इसलिए इनके राजनीतिक संदेश सीधे तौरपर प्रबुद्ध वर्ग, सरकारी कर्मचारियों और जमीनी संघटनकी मनोदशाको दर्शाते हैं। चूंकि ये चुनाव बैलेट पेपरसे हुए थे, इसलिए एनडीएकी इस जीतने विपक्षके उस नैरेटिवको बड़ा झटका दिया है जिसमें अक्सर ईवीएमपर सवाल उठाये जाते थे। भाजपाने इस नतीजेसे यह संदेश दिया है कि उसकी जीतका आधार जनताका समर्थन और मजबूत संघटन है, न कि वोटिंग मशीन। विधान परिषदके चुनावोंमें कांग्रेस 'बड़े शून्य' के धब्बेसे बच गयी। नागपुर स्नातक सीट जीतकर सभीको चौंका दिया। नागपुरकी जीत 'प्रतीकात्मक' है, क्योंकि यहां आरएसएसका मुख्यालय है और केन्द्रीयमंत्री नितिन गडकरी यहांसे सांसद हैं। महाराष्ट्रके मुख्य मंत्री देवेन्द्र फडणवीस भी नागपुरकी एक सीटसे विधायक हैं। क्या नागपुरमें स्नातक युवाओंपर संघ परिवारका मानसिक और नैतिक प्रभाव कम हुआ है। उत्तर प्रदेशमें प्रधान मंत्री मोदीके चुनाव क्षेत्र वाराणसीमें शिक्षक और स्नातक सीटें समाजवादी पार्टीने जीती हैं। इस सीटपर प्रधान मंत्रीकी सांसदके तौरपर जीतका अन्तर भी काफी कम हुआ था, लिहाजा यह भाजपाकी नयी चिन्ता होनी चाहिए कि शिक्षक और स्नातक जैसा शिक्षित वर्ग क्या भाजपासे विमुख हो रहा है। आगरामें भी सपाका उच्च जातियोंके बीच समीकरण बैठाना यह संकेत देता है कि भाजपाके कोर वोटर व्यापारी वर्गके भीतर स्थानीय स्तरपर कुछ नाराजगी है जिसे दूर करना भाजपाके लिए बड़ी चुनौती होगा। लखनऊ केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंहका चुनाव क्षेत्र है और गोरखपुर मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथका गृह-गढ़ है। लखनऊमें भाजपाकी पराजय हुई है और गोरखपुरमें 'दूसरी वरीयता' के स्तरपर मात्र ३०७ मतोंसे जीत पायी है। इलाहाबाद (अब प्रयागराज) भी भाजपाका गढ़ है। वहांसे भी सपाने जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेशमें मार्च, २०२७ में विधानसभा चुनाव होने हैं। बेशक विधान परिषदके चुनाव सीमित होते हैं, फिर भी हजारों मतदाता अपने मताधिकारका प्रयोग करते हैं। यह भी जनादेशसे कमतर नहीं माना जा सकता। कमोबेश इनके नतीजोंसे स्पष्ट संकेत मिलते हैं, लिहाजा दल सबक भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेशमें आम विधानसभा चुनावसे पहले ही समीकरण बदलते लग रहे हैं। यदि सपा-कांग्रेसने वाकई गठबंधनमें चुनाव लड़ा तो नतीजे अप्रत्याशित भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेशमें कुल ११ सीटोंमेंसे भाजपाके हिस्से छह और सपाके हिस्से पांच सीटें आयी हैं। भाजपा पिछले चुनावकी तरह ही है, लेकिन सपाने दो सीटोंकी बढ़त बनायी है, लिहाजा संकेत स्पष्ट हैं कि भाजपाके सामने चुनावी चुनौतियां हैं। सबसे चौंकाऊ नतीजा यह रहा है कि कर्नाटकमें कांग्रेसका सूपड़ा साफ हो गया है। सभी चारों सीटोंपर भाजपा-जद (एस) का कब्जा हो गया है। कर्नाटकमें कांग्रेस सत्तारूढ़ है। मुख्य मंत्री डीके शिवकुमार 'चुनावी सियासत' के चाणक्य माने जाते रहे हैं। बेंगलुरुमें पुट्टन्ना परिषदकी शिक्षक वर्ग सीटसे पांच बार निर्वाचित हो चुके हैं और परिषदके उपाध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन इस बार वह सीट जद-एसने छीन ली है। शेष तीनों सीटोंपर भाजपा विजयी रही है। यह २०२८ के विधानसभा चुनावके मद्देनजर 'बदलावका संकेत' है। बेंगलुरु शिक्षक सीट जैसे मजबूत गढ़